



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251]
No. 251]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 17, 2003/आश्विन 25, 1925
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2003/ASVINA 25, 1925

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2003

सं. 16-85/2003-एन आई-1/1(डी डी).—जबकि भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की विशेष समस्याओं और उनके लिए सम्मान का जीवन सुनिश्चित करने एवं सिविल सोसाइटी में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रति अवगत होते हुए निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूरी भागीदारी) अधिनियम, 1995, आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता एवं बहु-विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999, तथा भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 अधिनियमित किए हैं तथा यह सिविल सोसायटी, स्वैच्छिक संगठनों और सरकार के विभागों को शामिल करते हुए बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करती रही है।

2. तथा जबकि देश में विकलांग व्यक्तियों की अधिक आबादी और विकलांगता संबंधी मुद्दों के व्यापक स्वरूप पर विचार करते हुए इस समस्या के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की जरूरत हो गई है।

3. अतः अब एक राष्ट्रीय विकलांग जन आयोग का गठन करने का संकल्प किया गया है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो, जो विकलांगता और पुनर्वास संबंधी मामलों के संबंध में सरकार को सहायता और सलाह दे सके और इस संबंध में सिफारिशें कर सके।

तथा यह कि,

(क) आयोग में अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य, एक सदस्य - सचिव तथा पांच अन्य सह-सदस्यों सहित 9 सदस्य होंगे; तथा

(1) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य और सह सदस्य ख्यातिप्राप्त तथा विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास और अधिकारों के लिए हिमायत में शामिल व्यक्ति होंगे;

(2) अध्यक्ष/सदस्य/सह सदस्य में से तीन श्रवण विकलांग, दृष्टि विकलांग तथा चलन संबंधी विकलांग व्यक्तियों की श्रेणियों का अलग - अलग प्रतिनिधित्व करेंगे, एक सदस्य मानसिक मंदता से पीड़ित व्यक्तियों के माता - पिता/अभिभावकों के संघों से और एक सदस्य ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात या बहु-विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के माता-पिताओं/अभिभावकों में से नामित किया जाएगा;

(3) अध्यक्ष, सदस्य तथा सह-सदस्यों में से न्यूनतम दो महिलाएं होंगी;

(4) सदस्य तथा सह-सदस्य को वोट देने का अधिकार होगा।

तथा यह कि

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों (सदस्य-सचिव के मामले को छोड़कर) की नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि के लिए होगी। अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, यदि उचित समझा जाए तो एक अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे तथा त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु अथवा अन्य कारणों से उत्पन्न रिक्तियों को पूर्व पदधारी की शेष अवधि के लिए, यदि यह अवधि 6 महीने से अधिक है, नए नामांकन द्वारा भरा जाएगा।

तथा यह कि सभी सदस्य राष्ट्रपति के चाहने की अवधि तक पद धारित करेंगे और उस पद के उद्देश्यों और सम्मान के प्रतिकूल कार्यों तथा ऐसे अन्य आधार (आधारों) पर हटाए जा सकेंगे जिसे वे धारित किए हुए हैं, जैसा कि प्रावधान है।

तथा यह भी संकल्प किया जाता है कि

(ख) आयोग निम्नलिखित के लिए सक्षम होगा:-

- (क) विकलांग व्यक्तियों के लिए दर्जे, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को दूर करने के लिए कार्रवाई के विशेष कार्यक्रमों की सिफारिश केन्द्र सरकार को करना ताकि विकलांगताओं के बावजूद उनकी क्षमताओं का आकलन किया जा सके और उनकी मनोवैज्ञानिक - सामाजिक स्वीकृति तथा देश के सामाजिक और आर्थिक जीवन में पूर्ण भागीदारी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें सही शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा गरीबी उन्मूलन पैकेज, रोजगार तथा अन्य सहायक सेवाएं प्रदान की जा सकें;
- (ख) विकलांगता के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं की स्थिति और दशाओं की समीक्षा करना तथा सिफारिशें करना; तथा
- (ग) विकलांग व्यक्तियों से संबंधित मामलों पर अपनी सिफारिशों के साथ केन्द्र तथा राज्य सरकारों को वार्षिक रिपोर्ट देना;
- (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य करना ।

(ग) यह कि आयोग की तीन महीने में कम से कम एक और यदि अपेक्षित हो तो अधिक बार बैठक होगी ।

तथा यह कि आयोग को किसी विशेष विषय या मामले के संबंध में सूचना सहित ऐसी सूचना विकलांग व्यक्तियों के संबंध में कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित किसी सरकार, स्थानीय या अन्य प्राधिकरण से मांगने की शक्ति होगी जो उपर्युक्त कार्यों को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक होगी;

यह संकल्प भारत के राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से और नाम में ।

राजवन्त सन्धू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**RESOLUTION**

New Delhi, the 16th October, 2003

No. 16-85/2003-NI-1/1 (DD).—Whereas the Government of India, being seized of the special problems of persons with disabilities and of the need for ensuring a life of dignity for them and of ensuring their full participation in civil society, has enacted the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 and the Rehabilitation Council of India Act, 1992, and has been implementing several schemes through a multi-sectoral approach involving civil society, voluntary organizations and departments of the Government.

And whereas, considering the large number of disabled persons in the country and the magnitude of disability issues with all their ramifications, a need has arisen to take a holistic view of the problem;

Now, therefore, it is resolved to constitute a Commission to be called the National Commission for Persons with Disabilities, with its headquarters at New Delhi to aid and advise the Government regarding disability and rehabilitation matters and to make recommendations to it in this regard;

And that-

(A) the Commission shall consist of nine Members, including a Chairperson, two full time Members, a Member-secretary and five Associate Members; and

(i) the Chairperson, the full time members and the Associate Members shall be persons of eminence and involved in the rehabilitation and advocacy for the rights of persons with disabilities;

- (ii) *three* of the Chairperson/ Members/ Associate Members will separately represent the categories of persons with hearing impairment, visual impairment and locomotor disability and one each shall be nominated, from the Associations of Parents/ Guardians of persons suffering from mental retardation and Parents/ Guardians of persons suffering from autism, cerebral palsy or multiple disability;
- (iii) from among the Chairperson, Members and Associate Members, at least two shall be women;
- (iv) both Members and Associate Members shall have voting rights;

And that, the Chairperson and other Members shall be appointed by the Central Government for a term of three years (except in case of the Member-Secretary). The Chairperson and other members shall be eligible for reappointment for one additional term if deemed appropriate and a vacancy caused due to resignation, removal, death or otherwise shall be filled by fresh nomination for the remaining period of the earlier incumbent if this period is more than six months.

And that, all Members shall hold office during the pleasure of the President of India and shall be removable for actions inconsistent with the objectives and dignity of the office they hold and on such other ground(s) as provided.

And it is further resolved that-

(B) the Commission shall be competent to -

- (a) recommend to the Central Government specific programmes of action towards elimination of inequalities in status, facilities and opportunities for disabled persons so that they are assessed for their abilities despite disabilities and given the right education, vocational training and poverty alleviation packages, employment, and other support services to achieve

the goal of psycho-social acceptance and full participation in the social and economic life of the country;

(b) review the status and conditions of institutions delivering services in the disability sector and make recommendations; and

(c) make annual reports to the Central and State Governments on matters concerning disabled persons, with its recommendations.

(d) discharge any other work assigned by the Central Government from time to time.

(C) that, the Commission shall meet at least once in three months and more frequently, if required.

And that the Commission shall have the power to call for such information including information with respect to any specific matter or case, as may be necessary for the discharge of above functions from any Government, local or other authority concerned with the implementation of programmes and schemes in regard to disabled persons;

This Resolution shall come into force on and from the date of its publication in the Gazette of India.

By Order and in the name of the President of India.

RAJWANT SANDHU, Jt. Secy.